Ph.: Off.: 2633233/2955977
aryawani.ngp@gmail.com

|| ओ३म् ||

दयानन्द आर्य कन्या महाविद्यालय

आर्य विद्या सभा द्वारा संचालित
(Regd. under Societies Act. XXI)
जरीपटका, नागपुर ४४००१४.

Brief Report

Brief Report of Project / Field/ Internship Work (1.3.3)

Name of the Project Undertaken	" **Budget ki report** "	
Academic Session	2024-25	
Organizing Department/ Committee	Major Economics (SEC I Year)	
Total Number of Students Participated in the Project	19	
Brief Report	The Project entitled - " **Budget ki report** " undertaken by the Department of Economics during the session of 2024-25 under the guidance of Internal Quality Assurance Cell of the Institution. Total 10 students participated in the project activity and successfully completed the project. The completion certificate has been given to the students. All students found it very interesting to learn through the experiential learning. They enjoyed the project work.	
Criterion :1	Metric no-1.3.3	
Signature of Co-Ordinator Dr. Ritu Tiwari	Signature & Stamp of IQAC Co-Ordinator -IQAC Coordinator (Dr Mugdha Deshpande)	Principal (Prof Dr Sujata Chakravorty) Signature of & Stamp of Principal

Ph.: Off.: 2633233/2955977
aryawani.ngp@gmail.com

|| ओ३म् ||

दयानन्द आर्य कन्या महाविद्यालय

आर्य विद्या सभा द्वारा संचालित
(Regd. under Societies Act. XXI)
जरीपटका, नागपुर ४४००१४.

Students Information

S.N.	Name of Student	Program	Class
01.	Khushi Mithlesh Patle	B. A	I year
02.	Damini Vijay Kumar Rahangdale	B. A	I year
03.	Divya Madhavrao jambulkar	B. A	I year
O4.	Tannu Santosh dhkate	B. A	I year
05.	Sakshi Kailash Kanojiya	B. A	I year
06.	Sangeeta bhojraj Madavi	B. A	I year
07.	Raksha Sudhakar Bodhakar	B. A	I year
08.	Rishu shivdayal Chouhan	B. A	I year
09.	Sandhya Suresh Beriha	B. A	I year
10.	Khileshwari sukrita Shahu	B. A	I year
11.	Laxmi Sudhakar Avasarer	B. A	I year
12.	Divya Vijay Bahadur Yadav	B. A	I year
13.	Simranjeet Kumar Ranjeet Singh Sountre	B. A	I year
14.	Javeriya parvej Ahmad Khan	B. A	I year
15.	Meetali Anil Shendre	B. A	I year
16.	Nandini Anil Mishram	B. A	I year
17.	Vanshika T Nandanwar	B. A	I year
18.	Pranvi D Bhoyar	B. A	I year
19.	Kamini P Nehare	B. A	I year

Front Page of Project

Page No.

Date

Name: Khushi Mithlesh Patle

Class: B.A 1st Year

Subject: SEC (Budget)

Date: 11/03/25

College: Dayanand Arya Kanya Mahavidayalya Jaripatka Nagpur

ARYA VIDYA SABHA'S

DAYANAND ARYA KANYA MAHAVIDYALAYA

Jaripatka, Nagpur.

' Economics project'

Organised By

Department of project

CERTIFICATE

This is to certify that project work in the subject Major Eco (SEC) entitles Budget Ki Report hsa been successfully completed by ku. Khushi Mithlesh Patle of B.A I Year during the Academic session 2024-25 Hence the certificate is awarded to her.

Co-Ordinator
Dr. Ritu Tiwari
Dept. of Economics

Principal
Dr. Sujata Chakravorty
DAKM, Nagpur

Project copy

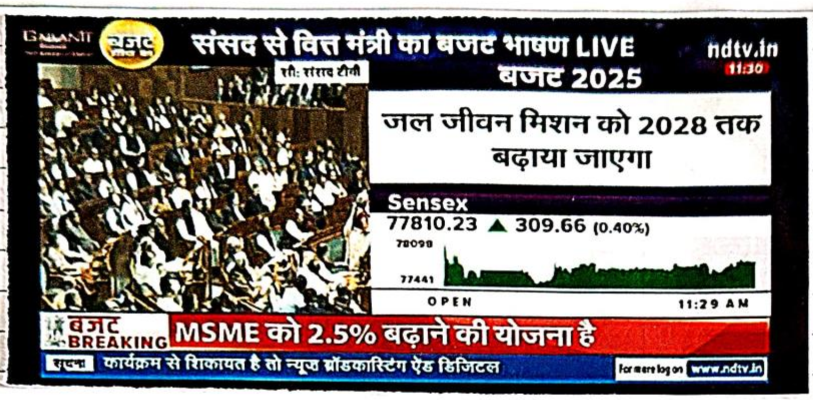

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया जिसमें उनके बजट भाषण का सारांश दिया गया है।

हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अधिक समृद्धि और वैश्विक स्थिति के लिए अपने देश की जबरदस्त क्षमता को उजागर करने की यात्रा पर चल पड़े हैं

तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुरजाडा अप्पा राव की प्रसिद्ध कहावत, एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी नहीं है; एक देश उसके लोग हैं को अपनाते हुए "सबका विकास" थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया

इस विषय के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं।

→ शून्य गरीबी

→ शत-प्रतिशत अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूल शिक्षा।

→ उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच

→ सार्थक रोजगार के साथ शत-प्रतिशत कुशल श्रमिक

→ आर्थिक गतिविधियों में सत्तर प्रतिशत महिलाएँ तथा

→ किसान हमारे देश को विश्व की खाद्य टोकरी बना रहे हैं।

* बजट अनुमान 2025-26

→ उधार के अलावा कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय क्रमश: ₹ 34.96 लाख करोड़ और ₹ 50.65 लाख करोड़ अनुमानित हैं।

→ राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है

→ वित्त वर्ष 2025-26 में ₹ 11.21 लाख करोड़ (जीडीपी का 3.1%) का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है

या मध्य वर्ग | विकसित भा

ूट का पैसा | और कितने क्र

के निवेश का क्या होगा

मन में उमंग में वसंत आ

भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा

■ दिल्ली, नवभारत न्यूज नेटवर्क. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 5.2 प्रतिशत की कम वृद्धि दर की स्थिति से तेजी से पटरी पर लौट रही है. उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहे. वित्त मंत्री ने लोकसभा में 2025-26 के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि बजट में राजकोष के मोर्चे पर सूझबूझ के साथ कदम उठाने के साथ लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाने के उपाय किये गये हैं. राजकोषीय सूझबूझ का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2025-26 में 99 प्रतिशत कर्ज का उपयोग पूंजीगत व्यय में किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि मुद्रास्फीति प्रबंधन इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और खुदरा महंगाई 2 से 6 प्रतिशत के संतोषजनक दायरे के भीतर है. विशेषकर खाद्य वस्तुओं की महंगाई का रुख कम होता दिख रहा है. सीतारमण ने जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि के बारे में कहा कि 2024-25 से पहले के 3 वर्षों में, देश की वृद्धि दर औसतन लगभग 8 प्रतिशत थी. देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो 4 साल में सबसे कम है. वित्त मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष 2025-26 में वृद्धि दर 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है. सीतारमण ने कहा कि 12 में से केवल 2 तिमाहियों में देश की वृद्धि दर 5.4 तक या उससे नीचे रही.

पटरी पर आ रहीं चीजें

मंत्री ने कहा कि मजबूत आर्थिक बुनियाद के कारण चीजें तेजी से पटरी पर आ रही हैं और हम ऐसे कदम उठाएंगे जो आगे चलकर हमारी अर्थव्यवस्था को पिछले कुछ वर्षों की तरह सबसे तेजी से बढ़ने में मदद करेंगे. हम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बने रहेंगे. सीतारमण ने कहा कि गांवों में अच्छी मांग के कारण चालू वित्त वर्ष में निजी अंतिम उपभोग व्यय 7.3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि निजी अंतिम उपभोग व्यय बाजार मूल्य पर जीडीपी का 61.8 प्रतिशत होने का अनुमान है जो 2002-03 के बाद से सबसे अधिक है. सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.48 लाख करोड़ रुपये है जो जीडीपी का 4.3 प्रतिशत है. सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 15.68 लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है जो जीडीपी का 4.4 प्रतिशत है.

कर्ज का पूरा उपयोग करेगी सरकार

सरकार प्रभावी पूंजीगत व्यय के लिए कर्ज के लगभग पूरे हिस्से का उपयोग कर रही है. यानी उधार राजस्व व्यय या प्रतिबद्ध व्यय के लिए नहीं है. यह केवल पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए है. वित्त मंत्री ने कहा कि वास्तव में, सरकार प्रभावी पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए कुल कर्ज का लगभग 99 प्रतिशत उपयोग करेगी. सीतारमण ने कहा कि बजट ऐसे समय आया है जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएं हैं और वैश्विक वृहद-आर्थिक माहौल में बदलाव हो रहा है तथा वैश्विक वृद्धि दर स्थिर और मुद्रास्फीति ऊंची बनी हुई है.पिछले 10 साल में दुनिया के परिदृश्य में काफी बदलाव आया है और बजट बनाना अब पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है. बजट राजकोषीय प्राथमिकताओं के साथ राष्ट्रीय विकास की जरूरतों को संतुलित करता है. सीतारमण ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट पर कहा कि विभिन्न वैश्विक और घरेलू कारक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य को प्रभावित कर रहे हैं. अक्टूबर 2024 और जनवरी, 2025 के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में 3.3 प्रतिशत की गिरावट आई है लेकिन यह गिरावट एशिया की अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं की तुलना में कम रही है. इस अवधि में दक्षिण कोरियाई वोन और इंडोनेशियाई रुपैया में क्रमश: 8.1 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत की गिरावट आई है.

Page No.
Date

A विकास का पहला इंजन है कृषि

- → प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना - कृषि जिलो का विकास कार्यक्रम
- → ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन का निर्माण
- → दालो की आत्मनिर्भरता
- → सब्जियो और फलो के लिए व्यापक कार्यक्रम
- → बिहार में मखाना बोर्ड
- → उच्च उपज वाले बीजो पर राष्ट्रीय मिशन
- → मत्स्य पालन
- → कपास उत्पादकता मिशन
- → केसीसी के माध्यम से उन्नत ऋण
- → असम में यूरिया संयंत्र

बजट में उत्पादकता बढ़ाने फसल विविधीकरण अपनाने फसलोपरांत भंडारण बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाने तथा दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए 100 जिलों को कवर करते हुए राज्यों के साथ साझेदारी में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई

इस बजट में मध्यम वर्ग पर खास ध्यान

वर्ष 2025-26 के लिए पेश बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के मध्य वर्ग की महत्ता को आखिरकार स्वीकार कर लिया है. अब तक आम बजट में 'ज्ञान' यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला की ही बारंबार राजनीतिक रट लगा करती थी, लेकिन इस बार इसमें मध्यवर्ग को भी जोड़ा गया है. सो इस बजट में मध्य वर्ग की बार-बार दुहाई देते हुए उसके आयकर की मौजूदा सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की एक बड़ी घोषणा की गई है. इसके साथ ही आयकर में व्यापक सुधार लाने वाला एक नया कानून भी सरकार अगले हफ्ते लाने जा रही है. यह कानून 1961 के आयकर कानून का स्थान लेगा. बजट की हेडलाइन में इस बार कृषि, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, शहरी विकास, कौशल विकास, स्टार्टअप, एमएसएमई और निर्यात सेक्टर की कुछ नयी स्कीमें, बढ़े आवंटन के साथ-साथ चुनावी साल में प्रवेश कर चुके बिहार के लिए भी कई सौगातें शामिल की गईं हैं. बजट की घोषणा के मुताबिक तकनीकी तौर पर 4 लाख तक की सालाना आमदनी के लिए शून्य कर, 4 से 8 लाख तक 5 फीसदी, 8 से 12 लाख तक 10 फीसदी, 12 से 16 लाख आय पर 15 फीसदी, 16 से 20 लाख आमदनी पर 20 फीसदी, 20 से 24 लाख आमदनी पर 25 फीसदी और उससे ऊपर 30 फीसदी आयकर का स्लैब निर्धारित किया गया है.

दलहन-तिलहन की सीधी खरीदी

बजट में दलहन तिलहन के उत्पादन को और प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विपणन परिषद द्वारा इनके उत्पादकों से सीधे क्रय किये जाने की नयी स्कीम की घोषणा के साथ कपास, मखाना के लिए नये मिशन की स्थापना, देश के 100 जिलों में किसानों के लिए विशेष धन-धान्य प्रोत्साहन योजना तथा असम में यूरिया के दो नये प्लांट स्थापित कर यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना प्रमुख है. इसी क्रम में क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को रूपांतरित इंटेरेस्ट सबवेन्शन स्कीम के तहत लोन सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है. बजट में एमएसएमई सेक्टर की महिमा फिर से दुहराते हुए एक नया राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन स्थापित करने की बात की गई है. इसके अतिरिक्त एमएसएमई को मिलने वाले बैंक लोन की बढ़ी सकल मात्रा को और गति प्रदान करने की बात कही गई है.

बिहार को दिया झुकता माप

कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में आर्टिफिशिएल इंटेलिजेन्स के नये सेन्टर फार एक्सीलेंस स्थापित करने की बात कही गई है. देश में स्कूल स्तर पर शोध व प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पचास हजार स्कूलों में अटल लैब बनाने की घोषणा भी शामिल है. बजट भाषण में एक राज्य जिसका बारंबार जिक्र हुआ, वह बिहार था. जाहिर है एनडीए शासित इस राज्य में इस साल नवंबर में चुनाव हैं और इस सरकार की साझेदार दल केन्द्र की सरकार में भी साझेदार है. अविकसित माने जाने वाले राज्य बिहार में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु यहां राष्ट्रीय फूड टेक्नोलाजी संस्थान स्थापित करने, बिहटा सहित कई जगह ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट परियोजना शुरू करने, कोशी में सिचाई परियोजना हेतु विशेष वित्तीय आवंटन इस बार के केन्द्रीय बजट की विशेषता रही. देश में पर्यटन को नये सिरे से प्रोत्साहित करने के लिए 50 नये पर्यटक केन्द्रों को विकसित करने के साथ साथ निजी क्षेत्र के साथ मेडिकल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का करीब बीस हजार करोड का व्यय करने का इरादा प्रदर्शित किया गया है. साल 2025-26 के आम बजट में देश की उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु उर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों व मोबाइल की बैटरी में प्रयुक्त कुल 12 क्रिटिकल धातुओं के घरेलू उत्पादन व इनके आयात को शुल्क मुक्त करने की एक महत्वपूर्ण पहल दर्शायी गई है. करीब 36 जीवन रक्षक दवाओं को पूर्ण आयात कर मुक्त कर दिया गया है. वरिष्ठ नागरिकों की टीडीएस सीमा पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख तथा टीसीएस सीमा सात लाख से बढ़ाकर दस लाख किये जाने की एक राहत भरी घोषणा प्रमुख है. कुल मिलाकर निर्मला सीतारमण का यह बजट मध्य वर्ग को खुश करने की चाशिनी से सराबोर है.

-मनोहर मनोज

Page No.
Date

श्रीमती सीतारमण ने संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये रखने की घोषणा की

केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा कि सरकार तुअर उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेगी (केंद्रीय एजेंसियां (नेफेड और एनसीसीएफ) किसानों से अगले चार वर्षों के दौरान जितनी भी दालें खरीदने की पेशकश की जाएगी, उन्हें खरीदने के लिए तैयार रहेगी

* एमएसएमई विकास का दूसरा इंजन
→ एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन
→ सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड
→ स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स
→ पहली बार उद्यम करने वालों के लिए योजना
→ फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए फोकस उत्पाद योजना
→ खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय
→ खाद्य प्रसंस्करण के लिए समर्थन
→ विनिर्माण मिशन – "मेक इन इंडिया" को आगे बढ़ाना

र बिल्डिंग सर्वाधिक
क्टर है। उसी तरह
फ्रास्ट्रक्चर के दायरे
बहुत जोर दिया है।
देश 'विकास भी,
लेकर चल रहा है।
लिए महत्वपूर्ण और
है। बजट में किसानो
है, ये कृषिक्षेत्र और
वस्था में नई क्रांति

कि 12 लाख रुपये
टैक्स से मुक्त कर
बहुत बड़ा फायदा
लेगा। इस बजट में
0 डिग्री फोकस है।
एक वाइब्रेंट प्रतियोगी
बजट में विशेष जोर

PM ने कहा, इस बजट में मेन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है।

'हमने मिडल क्लास को राहत देने के लिए टैक्स दरों में कमी की'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार ने बजट में आयकर स्लैब में फेरबदल किया है, जिससे अब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। टैक्स छूट में बढ़ोतरी 12 लाख रुपये तक करने से और 1 करोड़ लोग आयकर नहीं देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने कहा, सरकार ने लोगों की आवाज पर प्रतिक्रिया दी है। हमने मिडल क्लास को लाभ पहुंचाने के लिए कर दरों में कमी की है। वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा कि हमने राजस्व में होने वाली कमी (छूट के कारण) को देखते हुए कर राजस्व में मामूली उछाल की उम्मीद की है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले 75% लोग पहले ही नई व्यवस्था में आ चुके हैं। हमें उम्मीद है कि हर करदाता अंततः इसमें शिफ्ट होगा।

नहर में गिरी कार, 12 लोगों की मौत

■ NBT न्यूज, हिसार : हरियाणा के फतेहाबाद में घने कोहरे के कारण शुक्रवार की रात एक कार भाखड़ा नहर में गिर गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 साल के बच्चे और एक बुजुर्ग को बचा लिया गया। शनिवार सुबह 7 लोगों के शव सिरसा जिले में मिले। इनमें से 6 के शव कालुआना माइनर में मिले हैं। कार में कुल 14 लोग सवार थे। सभी पंजाब में एक शादी समारोह से लौट रहे थे। मौके पर शनिवार रात को ही पुलिस पहुंच गई थी। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया।

एक बच्चे और एक बुजुर्ग को बचाया गया

वित मंत्री ने 5 लाख महिलाओ, अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के पहली बार उद्यमी बनने वालो के लिए एक नई योजना शुरू करने की भी घोषणा की इसके तहत अगले 5 वर्षो के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

श्रीमती सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार भारत को 'मेड इन इंडिया' ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलौनो का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए एक योजना भी लागू करेगी उन्होंने कहा कि सरकार 'मेड इन इंडिया' को आगे बढ़ाने के लिए छोटे माध्यम और बड़े उद्योगो को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन स्थापित करेगी।

टाइम्स

ी या नहीं

GDP ग्रोथ पर टिकी है सारी प्लानिंग

Page No
Date

A विकास के तीसरे इंजन के रूप में निवेश

A→ लोगों में निवेश
- → सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0
- → अटल टिंकरिंग लैब्स
- → सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
- → भारतीय भाषा पुस्तक योजना
- → कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र
- → आईआईटी में क्षमता का विस्तार
- → शिक्षा के लिए एआई में उत्कृष्टता केंद्र
- → चिकित्सा शिक्षा का विस्तार
- → सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर
- → शहरी आजीविका को मजबूत बनाना
- → पीएम स्वनिधि
- → ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

निवेश को विकास का तीसरा इंजन बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश को प्राथमिकता दी

लोगों में निवेश के तहत, उन्होंने घोषणा की अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी

QUICK NEWS

बुनियादी ढांचे में होगा बड़ा बदलाव

दिल्ली. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के प्रबंध निदेशक पीआर जयशंकर ने रविवार को कहा कि इस साल के बजट से यह स्पष्ट है कि सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने की महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की है. उन्होंने बजट में की गई कुछ प्रमुख घोषणाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बजट में रेखांकित रणनीतिक निवेश और नीतिगत सुधार 2047 तक देश को विकसित करने, सतत आर्थिक वृद्धि, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. सरकार ने विभिन्न उपायों की घोषणा की है जिसमें परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना (2025-2030) भी शामिल है। इसका उद्देश्य नियामकीय और राजकोषीय सुधारों के माध्यम से नए बुनियादी ढांचे के विकास में 10 लाख करोड़ रुपये की राशि को वापस डालना है. उन्होंने कहा कि बजट में भूमि अभिलेखों, शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे की डिजाइन को आधुनिक बनाने, परियोजना निष्पादन दक्षता बढ़ाने के लिए पीएम गतिशक्ति का लाभ उठाने की योजना की भी घोषणा की गई है.

उन्होंने कहा कि स्कूल और
उच्च शिक्षा के लिए भारतीय
भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल
रूप में उपलब्ध कराने
के लिए भारतीय भाषा
पुस्तक योजना लागू
की जाएगी

त मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी

जीएसटी में औसत कर दर 15.8% से घटकर 11.3%

■ दिल्ली, नवभारत न्यूज नेटवर्क. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया कि वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के तहत अप्रत्यक्ष कर इसके लागू होने के बाद से पिछले कुछ वर्षों में काफी कम हुआ है. उन्होंने कहा कि पिछली अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत औसत कर 15.8 प्रतिशत था, जीएसटी के तहत यह अब घटकर 11.3 प्रतिशत हो गया है. पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) के सांसद नदीमुल हक की ओर से उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए, वित्त मंत्री ने ने समय के साथ जीएसटी दरों में कमी की जानकारी दी. वित्त मंत्री ने कहा कि पहले रोजमर्रा की वस्तुओं पर 15.8 प्रतिशत कर लगाया जाता था. अब जीएसटी के तहत दरें घटकर 11.3 प्रतिशत हो गई है. सीतारमण ने कहा कि जीएसटी के तहत एक भी वस्तु पर कर नहीं बढ़ा है, बल्कि कई वस्तुओं पर कर कम हुआ है. सत्र के दौरान सांसद हक ने यह भी पूछा कि क्या सरकार आयकर में किए गए सुधारों के समान कर स्लैब की संख्या को कम करके जीएसटी संरचना को सरल बनाने की योजना बना रही है.

मंदी से डरी सरकार का आय व रोजगार बढ़ाने पर फोकस

सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उठा सकती है कई कदम

■ दिल्ली, नवभारत न्यूज नेटवर्क. अर्थव्यवस्था की धीमी गति को देखते हुए, मांग को प्रोत्साहन देने और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई उपायों की घोषणा की संभावना है. चर्चा से जुड़े लोगों के अनुसार इन उपायों में मध्यम वर्ग को कर राहत, उद्योग को प्रतिकूल बाहरी वातावरण से बचाने के लिए टैरिफ उपाय, रोजगार सृजन और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की पहल शामिल हो सकती है. प्रधानमंत्री कार्यालय में पिछले हफ्ते हुई एक बैठक में बजट के व्यापक पहलुओं पर चर्चा की गई और अधिक विवरण तय करने के लिए आगे और बैठकें होंगी. अगले वित्त वर्ष का बजट (2025-26) 1 फरवरी को पेश किया जाएगा.

महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी जीत से उत्साहित नरेंद्र मोदी सरकार बजट में एक मजबूत संदेश देना चाहती है कि उसका सुधारों, व्यापार और जीवन की सुगमता पर फोकस है.अर्थव्यवस्था की आज जो स्थिति है उससे सरकार के भीतर यह धारणा बढ़ रही है कि इस बजट से एक मजबूत संकेत जाना चाहिए. भारत की आर्थिक वृद्धि इस वित्त वर्ष में चार साल के निचले स्तर 6.4% तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे मांग और निवेश को प्रोत्साहित करने के उपायों की आवश्यकता महसूस हो रही है. विचाराधीन कर उपायों में नई कर व्यवस्था के तहत आम लोगों के लिए राहत, कॉरपोरेट कर का सरलीकरण और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) व्यवस्था को आसान बनाना शामिल है. बीजेपी के भीतर से भी नई कर व्यवस्था के तहत स्लैब को और व्यापक बनाने की मांग उठी है, क्योंकि शहरी खपत धीमी पड़ने लगी है. इस पर अंतिम निर्णय अगले कुछ दिनों में लिया जाएगा.

कर संग्रह और बजट पर प्रभाव

12 जनवरी तक

15.88% की वृद्धि शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में

₹16.90 लाख करोड़ तक पहुंच गया है यह

₹ 8.74 लाख करोड़ है व्यक्तिगत आयकर संग्रह

15 लाख की आय पर लागू होता है 30% का स्लैब

आयकर दरों में कमी धीमी होती शहरी मांग को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकती है.

रोजगार और निवेश पर ध्यान

जुलाई बजट में घोषित तीन रोजगार-संबंधित प्रोत्साहन योजनाओं के आधार पर रोजगार सृजन को समर्थन देने के लिए कुछ फॉलोअप उपाय भी संभव हैं. चुनावों के कारण मौजूदा वित्तीय वर्ष में कमजोर रहे केंद्र के पूंजीगत व्यय को बजट में बढ़ावा मिलने की संभावना है, ताकि निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके. मौजूदा वित्त वर्ष में निवेश का एक उपाय सकल स्थिर पूंजी निर्माण 6.4% बढ़ने का अनुमान है जो पिछले वर्ष 9.2% था.

टैरिफ और राजकोषीय संतुलन

चीनी वस्तुओं की डंपिंग की आशंकाओं के बीच उद्योग को सस्ते आयात के हमले से बचाने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी में बदलाव की संभावना है. विदेशी निवेश व्यवस्था को आसान बनाने के उपायों पर भी चर्चा हुई है और इसे बजट में शामिल किया जा सकता है.आर्थिक प्रोत्साहन की आवश्यकता को देखते हुए राजकोषीय कंसोलिडेशन रोडमैप में कुछ बदलाव हो सकता है. सरकार ने अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% तक घटाने का वादा किया है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में 4.9% के रूप में बजट किया गया है.